योजना (1980–85) के प्रारूप में, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया, पिछले तीस वर्षों में गरीबी को दूर करने में हुई प्रगति की समीक्षा की गई है और योजना की अवधि में प्रस्तावित गरीबी प्रतिरोधक कार्यक्रम दिए गए हैं। इस योजना के प्रारूप की दस प्रतियां संदर्भ के लिए संसद के पुस्तकालय में पहले से उपलब्ध हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 5.2 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि दर के लिए व्यवस्था की गई है। अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि की समग्र दर में पर्याप्त वृद्धि से ही गरीबी में कमी के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा, गरीब वर्गों को सीधे सहायता देने के लिए विशिष्ट स्कीमें शुरू की जाएंगी। इस योजना में शामिल की गई कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं —एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 3,486.77 करोड़ रुपये है। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 5808 करोड़ रु० का परिव्यय भी आवंटित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप यह अनुमान है कि गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों का प्रतिशत 1979–80 में लगभग 48 प्रतिशत से कम होकर 1984–85 में 30 प्रतिशत हो जाएगा।

(ग) 1979–80 में गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों की संख्या के सामान्य रूप से 3168.4 लाख होने का अनुमान है।

Strike in Budhal Mines in District Rajnandgaon

378. SHRI SHIVENDRA BAHADUR SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the strike conducted by the leaders in the Budhal Mines in District Rajnandgaon; and

(b) what steps Government have taken to absorb their temporary labour for permanent jobs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAMDULARI SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) The strike was called off and a memorandum of Settlement was signed by the management and the workers. In accordance with the settlement, the workers shall be classified as per classification given in the Model Standing Orders which *inter alia* provide that such workers as have been engaged on permanent basis and have satisfactorily completed the probationary period of three months, shall be classified as permanent.

Un-willingness by entreprenuers to invest in Assam

379. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether entrepreneurs are not willing to invest in Assam due to the existing turmoil in the State; and

(b) if so, the steps Government propose to adopt to remove reluctance on the part of the entrepreneures and bring accelerated industrial development of the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) The agitation in Assam on the foreigners' issue started in August-September, 1979 has continued for over 18 months. Ferquent bundhs, gheraos, non-cooperation, hungerstrike and satyagrah resorted to during the agitation have generated an atmosphere of tension, surcharged with communal overtones, which has engulfed the entire State. Frequent bundhs and picketing have disrupted the normal Economic activity throughout the State.

(b) Government have recently decided to enhance the quantum of